

व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि - चूली तेल का निष्कर्षण

द्वारा

दबला - स्वयं सहायता समूह



एस एच जी/सी आई जी नाम	:: दबला
वी एफ डी एस नाम	:: सियाशो
श्रेणी	:: पूह
विभाजन	:: किन्नौर

इसके तहत तैयार:



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1	एस एच जी/सी आई जी का विवरण	3
2	लाभार्थियों का विवरण	4
3	गांव का भौगोलिक विवरण	5
4	कार्यकारी सारांश	5
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	5
6	उत्पादन योजना	5-6
7	बिक्री और विपणन	6
8	संकट विश्लेषण	6
9	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	6
10	अर्थशास्त्र का विवरण	6-7
11	आय और व्यय का विश्लेषण	7
12	निधि की आवश्यकता	8
13	निधि के स्रोत	8
14	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	8
15	ऋण चुकौती अनुसूची	8-9
16	निगरानी विधि	9
17	टिप्पणी	9
18	समूह सदस्यों की तस्वीरें	9-10

1. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	एसएचजी/सीआईजी नाम	::	डबला
2.2	वी एफ डी एस	::	सियाशो
2.3	श्रेणी	::	मॉलिंग
2.4	विभाजन	::	किन्नौर
2.5	गाँव	::	सियासू
2.6	अवरोध पैदा करना	::	कानम
2.7	ज़िला	::	किन्नौर
2.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	13 महिला
2.9	गठन की तिथि	::	03-12-2022
2.10	बैंक खाता सं.	::	
2.11	बैंक विवरण	::	
2.12	एस एच जी/सीआईजी मासिक बचत	::	50 (बैठक प्रत्येक माह के तीसरे दिन आयोजित की जाएगी)
2.13	कुल बचत		
2.14	कुल अंतर-ऋण		-
2.15	नकद क्रेडिट सीमा		--
2.16	पुनर्भुगतान स्थिति		--

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम (श्री/श्रीमती)	पिता/पति का नाम (श्री)	आयु	वर्ग	आय स्रोत	पद का नाम	संपर्क नं.
1.	श्रीमती कमला देवी	श्री रतन सागर	37	अनुसूचित जनजाति	कृषि	प्रधान	9418593762
2.	श्रीमती नीतू बिष्ट	श्री सुशील कुमार	35	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सचिव	8988051165
3.	श्रीमती जानुका	श्री.छेरिंग डंडुप	45	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459823541
4.	श्रीमती कुसुम लता	श्री प्यारे लाल	39	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459566141
5.	श्रीमती हुकुम मणि	श्री.छेरिंग राम	56	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459823546
6.	श्रीमती सुमेधा कुमारी	श्री सुन्दर सिंह	55	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459823415
7.	श्रीमती दीपिका कुमारी	श्री नारायण सिंह	32	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459800451
8.	श्रीमती सरकुम जंगमो	श्री नरेश कुमार	53	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9418394893
9.	श्रीमती कांता देवी	श्री बेली राम	76	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9418300407
10.	श्रीमती ललिता कुमारी	श्री ज्ञान जीत	48	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	9459980331
11.	श्रीमती विक्रमा देवी	श्री राजेंद्र कुमार	38	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	8988112534
12.	श्रीमती प्रेम बाघती	श्री गोपाल सिंह	58	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	8988275916
13.	श्रीमती द्वा डोलमा	श्री राम सिंह	76	अनुसूचित जनजाति	कृषि	सदस्य	-

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	70 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	एनएच 5 से 5 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	रिकांगपिओ-70 किमी, पूह -14 किमी रामपुर 170 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	रिकांगपिओ-70 किमी, रामपुर 170 किमी
3.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	रिकांगपिओ-70 किमी, रामपुर 170 किमी
3.6	उन स्थानों/स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	रिकांगपिओ-70 किमी, पूह -14 किमी रामपुर 170 किमी

4. कार्यकारी सारांश

सियासो गांव किन्नौर जिले के पूह उपमंडल में आता है। स्थानीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय बागवानी और कृषि है। चूंकि यह क्षेत्र बागवानी क्षेत्र में स्थित है और अधिकांश लोग इसी गतिविधि में लगे हुए हैं। सेब के अलावा लोग चुली (खुबानी) जैसे गुठलीदार फलों की भी खेती कर रहे हैं। चुली (खुबानी) के बीजों का इस्तेमाल लोग तेल निकालने के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में पूरी प्रक्रिया कच्चे माल को कनम पूह और आर/पीओ में स्थित कोहलू में ले जाने के माध्यम से होती है। इसलिए, गांव में ही तेल निकालने के लिए सियासो गांव के लोगों ने इस गतिविधि को आय सृजन गतिविधि के रूप में अपनाने की इच्छा जताई। तदनुसार, लोगों को जागरूक किया गया और एक स्वयं सहायता समूह दाबला का गठन किया गया।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1.	उत्पाद का नाम		चुल्ली तेल
2.	उत्पाद पहचान की विधि		यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तय की गई है।
3.	एस एच जी/सी आई जी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति		हाँ

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	समय लिया	::	यह गतिविधि मौसमी आधार पर की जाएगी
6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	13.

6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	गांव स्वयं
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
6.5	अपेक्षित मात्रा प्रति दिन	::	50 किलोग्राम बीज से 23 लीटर प्रतिदिन उत्पादन होता है।

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार स्थान/स्थान	::	गांव स्वयं, पूह, रिकांगपिओ और रामपुर
7.2	माँग	::	साल भर।
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आस-पास के गांवों/बाजार से संपर्क करेंगे
7.4	विपणन रणनीति		स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे निकटवर्ती गांवों/बाजार से ऑर्डर लेंगे।

8. संकट विश्लेषण

- कौशल आधारित
- मांग संचालित
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

- कुछ समूह सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया (अर्थात् कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और विपणन में शामिल होंगे।

10. अर्थशास्त्र का विवरण:

एक।	पूँजीगत लागत			
क्रमांक	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (₹.)
1	तेल निकालने की मशीन	1	80,000	80,000
2	टोपी, दस्ताने आदि	एल/ एस	एल/एस	5000
3	अलमारी	1	रास	5000

4	कुर्सियां, मेज आदि	लगभग।	रास	5000
	कुल पूंजी लागत (ए) =			95,000

बी।	आवर्ती लागत				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	कीमत	कुल राशि (रु.)
1	स्थानीय बाजार से चूली का कच्चा माल	किलोग्राम	1000	300	300000
2	प्लास्टिक की बोतलें (200 एमएल, 500 एमएल, 750 एमएल)	नहीं।	2500	10	25000
3	किराया	महीना			1500
4	अन्य (स्टेशनरी, बिजली बिल, परिवहन, मशीन मरम्मत)	महीना			10000
कुल आवर्ती लागत (बी)					3,36,500

सी।	उत्पादन लागत (मासिक)	
क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	कुल आवर्ती लागत	336500
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यहास	955
	कुल	3,37,455

डी।	विक्रय मूल्य				
क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)
1	चूली तेल	ले	1	1500	1500

11. आय और व्यय का विश्लेषण (महीने के):

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
1	पूंजीगत लागत पर 10% मासिक मूल्यहास	955
2	कुल आवर्ती लागत	3,36,500
3	प्रति माह निकाले गए तेल की कुल मात्रा	460 लीटर (लगभग मात्रा)
4	तेल का विक्रय मूल्य	1500

5	आय सृजन (460*1500)	6,90,000
6	शुद्ध लाभ (690000 - 337455)	3,52,545
7	शुद्ध लाभ का वितरण	• लाभ मासिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। • लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा • समूह को कुछ आय ग्रामीणों से लिए जाने वाले निष्कासन शुल्क से प्राप्त होगी, क्योंकि क्षेत्र के प्रत्येक घर में चूली के बीज निकालने के लिए उपलब्ध हैं तथा वर्तमान में यह कार्य रामपुर से किया जा रहा है।

12. निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	95,000	71,250	23,250
2	कुल आवर्ती लागत	336500	0	336500
3	प्रशिक्षण	40000	40000	0
	कुल	4,71,500	1,11,250	3,60,250

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत -परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 75% तथा स्वयं सहायता समूह को 25% कवर किया जाएगा।
- आवर्ती लागत -एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

13. निधि के स्रोत:

भारप्रोजेक्टसपोर्ट;	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	शीनों की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
---------------------	--	---

सएचजी योगदान	- पूँजीगत लागत का 75% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। - आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	
--------------	--	--

14. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

15. ऋण चुकौती अनुसूची-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है, तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

16. निगरानी विधि -

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

17. टिप्पणी

समूह सदस्यों की तस्वीरें-



द्वा डोलमा



हुकम मोनी



कमला देवी



प्रेम भगति



सरकुम जंगमो



विक्रमा देवी



ललिता कुमारी



नीतू बिष्ट



दीपिका कुमारी



सुमेधा कुमारी



कांता देवी



जानुका देवी



कुसुम लता

समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक 18-01-2023 डाबला स्वयं सहायता समूह श्यासो में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्रीमति कमला देवी के अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में यह चर्चा की सभी सदस्य ने यह निर्णय लिया की जायका वन विभाग की तरफ से जो धनराशी मिलेगी उसका उपयोग चुली का तेल निकालना सीखने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों की सहमती प्रकट की है। इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

कमला देवी

समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

प्रधान
डाबला स्वयं सहायता समूह
ग्राम शिवासो ते0 पहा, जिला
किन्नोर, दिक्काल पदक

नीतू छिष्ट

समूह के सचिव के हस्ताक्षर

प्रधान
डाबला स्वयं सहायता समूह
ग्राम शिवासो ते0 पहा, जिला
किन्नोर, दिक्काल पदक

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The SIASHO Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee
And

The Forest Department (represented by DFO KINNAUR for Participatory Forest Management.

Whereas

The SIASHO Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of SIASHO village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district KINNAUR and Forest Division KINNAUR, Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),

as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called "Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The KINNAUR Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

~~This Memorandum of Understanding (hereinafter called "MoU") details the responsibilities of the~~
Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2) Responsibilities of the Society

- 2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.
- 2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.
- 2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.
- 2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.
- 2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.
- 2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.
- 2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.
- 2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.
- 2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.
- 2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.
- 2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.
- 2.12. ~~The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the~~

- ☞ Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.
- 2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.
- 2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).
- 2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.
- 3. Responsibilities of the Forest Department**
 - 3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.
 - 3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)
 - 3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.
 - 3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.
 - 3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.
 - 3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).
- 4. Support by the Project**
 - 4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&L guidelines, which will be implemented by the Society.
 - 4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.
 - 4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.
 - 4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

- 4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation, Biodiversity conservation etc., will be credited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan) of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.
- 4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.
- 5. Rights and Benefit Sharing**
- 5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.
- 5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:
- i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non-timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;
 - ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;
 - iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;
 - iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;
 - v) after 5 years, the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;
 - vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.
- provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.
- 5.3. The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling, whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,
- 6. Monitoring & Evaluation**
- 6.1. Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.
- 6.2. The EC of VFDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

- 6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.
- 6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for that activity.
- 6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I RATTAN KUMARI ..., President, SIA SHO Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

रमेश कुमार
(Name and Signature of the President)
On behalf of VFD/BMC (Sub-committee)

G.A.
Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. *Sevitra Devi*
2. *Kanta Devi*
3. *Yantan Mohi*
4. *Yogita*

Yogita
Kanta
Yantan
Yogita

1 _____, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

R. F. O. POOH
Range Forest Officer
Pooh Range

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

G.A.
Kinnaur Forest Division
At R/Peo

Business Plan Approval by VFDS & DMU

----- DABLA ----- Self help group will undertake the ----- Chuli oil -----
As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh
Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan
of amount (Rs.) ----- 336,500 ----- has been submitted by this group on dated -----
----- and this business plan has been approved by ----- STASHO ----- VFDS. Business
Plan with SHG resolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thankyou

रत्न कुमारी
प्रधान अध्यक्ष
Signature of VFDS Pradhan
स्थानीय, तहसील, जिला किन्नौर हिमाचल

सचिव अध्यक्ष
ग्राम वन विकास समिति स्थानीय
तहसील, जिला किन्नौर (हिमाचल)
Sheela Kumari
Signature of VFDS Secretary

[Signature]
Signature of Forest Guard

[Signature]
Signature of Block forest officer

[Signature]
R: F. O. POCH
Signature of Range Forest officer

Approved

[Signature]
DMU -cum-
Deputy conservator forests,
Kinnaur Division at R/Peo

Resolution -cum-group consensus form

It is decided in the general house meeting of the Self Help Group. DABLA..... Held on
..... at SIASHO..... that our self help group will undertake the
Chuli oil..... as livelihood income generation activity under the project for
improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted.)

Kanlatavi
Signature of Group Pradhan

प्रधान
संघ
डबला स्वयं सहायता समूह
राज सिमरने नो पुर, जिला
हिमाचल प्रदेश

NITU Bishb
Signature of Group Secretary

सचिव
डबला स्वयं सहायता समूह
राज सिमरने नो पुर, जिला
हिमाचल प्रदेश